दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 04 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 213

महत्वपूर्ण एवं खास

केन्द्र ने राज्यों को अब तक 16 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके फ्री उपलब्ध कराई

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ सरकार के सर्वांगीण दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदार और त्वरित चरण रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। नए पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 16.54 करोड़ से अधिक टीके की खुराक प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 15,79,21,537 खुराक हैं (आज सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक)। अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 75 लाख से अधिक खुराक (75,71,873)उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 59 लाख से अधिक (59,70,670) खुराक मिलेगी।

पाक सेना ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन

जम्मू (आरएनएस)। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास गोलीबारी करके संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन किया। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए इस साल 25 फरवरी को नया समझौता हुआ था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान ने पहली बार संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन किया है। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक एनएस जमवाल ने यहां कहा, 'पाकिस्तान रेंजर्स ने रामगढ़ क्षेत्र में तड़के सवा 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना उकसावे के गोलीबारी की। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी बलों ने बाड़ के पास गश्त कर रहे दल पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास और अन्य सेक्टरों में संघर्ष विराम के लिए फरवरी को हुए समझौते का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई थी।

केन्द्र सरकार की पॉलिसी पैरलाइजड हैः राहुल

नईदिल्ली (आरएनएस)। देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच वैक्सीन पर विपक्ष और राज्यों की राजनीति तेज़ हो गई है. महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों ने पहले ही वैक्सीन की कमी की बात कह दी है. इस बीच प्रधानमंत्री ने एक मई से 18 साल के उपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के अनुमति दे दी. अब इसी मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, सरकार की पॉलिसी पैरलाइजड है. इस पॉलिसी के साथ वायरस पर जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती. सरकार को इस बात को स्वीकार्य लेना चाहिए. उन्हें नकली बनने की जगह हालात का सामना करना पड़ेगा.

देश में कोरोना संक्रमित के नए मामलों में गिरावट... पिछले एक दिन में आए 3.68 लाख से ज्यादा नए मरीज, 3,417 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोरोना संक्रमण के प्रकोप की दूसरी नई लहर का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पिछले एक दिन में दैनिक मामलों में गिरावट आने से कुछ राहत मिली है। जबकि कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के लगतार बढ़ते आंकडे में अब भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर है, जहां सर्वाधिक मौते हुई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 3,68,147 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,99,25,604 हो गई है। पिछले एक दिन में 3,417 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है, जिससे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,18,959 पहुंच गई। भारत में मौतों की यह संख्या दुनिया के तीसरे स्थान पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका में 591,062 लोगों की मौत, दूसरे नंबर ब्राजील में 407,775 मौतें और तीसरे नंबर पर भारत में 2,18,959 लोगों की मौत हुई हुई है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस देश पर कहर बनकर टूटा है। इस दौरान 26 लाख से अधिक मामले सामने आए। सात दिनों में जानलेवा वायरस से करीब 23,800 लोगों की मौत हुई। वहीं शुक्रवार को कुल मामले 4 लाख के पार पहुंच गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय यह मान रहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप का ही कारण है कि देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है और

सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है।

कोरोना को मात देने वालों में इजाफा- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 15 फरवरी के बाद से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में यह भी बड़ी राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में 3,00,732 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और देश में अब तक 116,29,3003 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर 34,13,642 पहुंच गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे अधिक भारत में है।

महाराष्ट्र में सर्वाधिक संक्रमण के मामले- मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 56,647 नए मामले आए तथा 669 और लोगों की मौत होने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 47,22,401 और मृतक संख्या 70,284 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 51,356 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में 6,68,353 उपचाराधीन मरीज हैं। अब तक 39,81,658 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संबंधी 2,57,470 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,76,52,758 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

कोरोना के सक्रिय मरीज अब भी चुनौती- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दैनिक मामलों में कमी के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि विश्लेषण के लिहाज से यह बहुत शुरुआती संकेत हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद अब भी चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 12 राज्यों में एक लाख से अधिक मरीज कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में हैं। सात राज्यों में 50 हजार से एक लाख मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं, जबकि 17 राज्यों में संक्रमण के 50,000 से कम मरीज उपचाराधीन हैं।

टीकाकरण करने वालों की संख्या 16 करोड़ के नजदीक - देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 15,71,98,207 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बता दें कि 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 12 राज्यों ने एक मई से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी यह सभी राज्यों में शुरू नहीं हुआ है।

ममता बनर्जी ने पत्रकारों को दिया कोरोना योद्धा का दर्जा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश इस समय कोरोना वायरस महामारी में भी लगातार काम कर रहे राज्य के मीडियाकर्मियों को कोविड योद्धा घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के इस ऐलान से पहले राज्य ऐसा ऐलान कर चुके हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सोमवार को कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में वास्तविकता को जन-जन तक पहुंचाने वाले पत्रकार भी वास्तव में कोरोना योद्धा हैं।

ओडिशा में भी हुआ ऐलान - कोरोना काल के दौरान ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को राज्य के पत्रकारों को अग्रिम मोर्चा का कोविड योद्धा घोषित किया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि पत्रकार निर्बाध रूप से खबरें देकर और लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों से अवगत कराकर राज्य की बहुत सेवा कर रहे हैं। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी पत्रकारों के साथ-साथ जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी द्वारा सत्यापित गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों (प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक एवं बेव मीडिया आदि) को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन कर्मियों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का बनेगा नया आशियाना

» सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे आवास

नई दिल्ली (आरएनएस)। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है, इस परियोजना के तहत देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नया आशियाना भी मई से दिसंबर 2022 के बीच बनकर तैयार हो जाएगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) की इस जानकारी के अनुसार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट

को पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञों की ओर से प्रोजेक्ट को सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब यह बिल्डिंग अगले साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस बिल्डिंग में एक केंद्रीय सचिवालय और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) बिल्डिंग भी शामिल है।सीपीडब्लूडी की ओर से मंत्रालय को बताया गया है कि नए संसद भवन का काम नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भवन का काम मई 2022 तक पूरा होगा और प्रधानमंत्री आवास के साथ ही एसपीडी बिल्डिंग दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार होगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 13 हजार 450 करोड़ रुपये हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में नया संसद भवन तैयार किए जाने का लक्ष्य है। बता दें कि 2022 में भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। हालांकि, यह पूरा प्रोजेक्ट साल 2024 में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 11 प्रशासनिक भवन भी बनाए जाने हैं, जिसमें सभी मंत्रालय स्थित होंगे। लोकसभा हॉल में 1,272 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिनकी क्षमता क्रमशः 888 और 384 सीटों की होगी। इनका निर्माण 2026 में होने वाले संसद के सदस्यों में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लोकसभा हॉल में 1,272 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा ताकि संयुक्त सत्र का आयोजन किया जा सके।

देश में मौजूदा टीका नीति पर गौर करे केंद्र सरकारः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 मूल्य नीति पर फिर से गौर करने का निर्देश देते हुए कहा है कि पहली नजर में इससे लोक स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक नतीजे होंगे।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि आज की तारीख में निर्माताओं ने दो अलग कीमतों का सुझाव दिया है। इसके तहत, केंद्र के लिए कम कीमत और राज्य सरकारों को टीके की खरीद पर अधिक कीमत चुकानी होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नए निर्माताओं को आकर्षित करने के नाम पर निर्माताओं के साथ

बातचीत के लिए बाध्य करने से टीकाकरण वाले 18 से 44 साल के उम्र समूह के लोगों के लिए गंभीर नतीजे होंगे। पीठ ने कहा कि आबादी के अन्य समूहों की तरह इस उम्र समूह में वे लोग भी शामिल हैं जो बहुजन हैं या दलित और हाशिए के समूहों से संबंधित हैं। हो सकता है कि उनके पास भुगतान करने की क्षमता नहीं हो। पीठ ने कहा कि जरूरी टीके उनके लिए उपलब्ध होंगे या नहीं यह हरेक राज्य सरकार के इस फैसले पर टिका होगा कि वह अपने वित्त पर निर्भर करता है या नहीं, यह टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए या नहीं और सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं और दी जाए तो किस सीमा तक। इससे देश में असमानता पैदा होगी। नागरिकों का किया जा रहा टीकाकरण जनता की भलाई के लिए है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो समान हालात का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार 45 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी के लिए मुफ्त टीके प्रदान करने का भार वहन करेगी, राज्य सरकारें 18 से 44 आयु वर्ग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी, ऐसी वाणिज्यिक शर्तों पर वे बातचीत कर सकते हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा नीति की संवैधानिकता पर हम कोई निर्णायक फैसला नहीं दे रहे हैं लेकिन जिस तरह से मौजूदा नीति तैयार की गयी है उससे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जन स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक परिणाम होंगे। पीठ ने कहा कि इसलिए हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष बराबरी) और अनुच्छेद 21 (जीवन की सुरक्षा और निजी स्वतंत्रता) के पालन के साथ केंद्र सरकार को अपनी मौजूदा टीका नीति पर फिर से गौर करना चाहिए। वर्तमान में लोगों को 'कोविशील्ड' और 'कोवैक्सीन' टीके की खुराकें दी जा रही है।कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक सेवा और आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में ये निर्देश दिये हैं।

सरकारी एजेंसियों ने करीब 70 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीदी पूरी की

नईदिल्ली (आरएनएस)। चालू रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2021-22 में भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। चालू आरएमएस खरीद कार्रवाई से लगभग 28.80 लाख गेहूं उत्पादक किसान पहले ही लाभ प्राप्त कर चुके हैं। चालू आरएमएस 2021-22 के दौरान लगभग 17,495 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। यह पहला मौका है कि पंजाब के किसान गेहूं बिक्री के एवज में सीधे अपने खातों में भुगतान राशि प्राप्त कर रहे हैं। गेहूं खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। 02 मई तक 292.52 एलएमटी से अधिक की खरीद की गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 एलएमटी से लगभग 70 प्रतिशत अधिक खरीद है। 02 मई तक कुल 292.52 एलएमटी गेहूं खरीद में से पंजाब का योगदान 114.76 एलएमटी (39.23 प्रतिशत), हरियाणा 80.55 एलएमटी (27.53 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश का योगदान 73.76 एलएमटी (25. 21 प्रतिशत) रहा है। 30 अप्रैल तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9628.24 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं।

रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 76 टैंकर में 1125 मीट्रिक टन एलएमओ पहुंचाया

नईदिल्ली (आरएनएस)। सभी बाधाओं पर काबू पाने के साथ नए हल तलाशते हुएभारतीय रेल देश भर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) पहुंचाकर राहत प्रदान करने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। अब तक भारतीय रेल ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 76 टैंकरों में 1125 एमटी (लगभग) एलएमओ पहुंचाया है। 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है एवंसात और लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस 27 टैंकरों में 422 एमटी (लगभग) एलएमओ ले जा रही हैं। भारतीय रेल कोशिश कर रहा है कि अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक एलएमओ पहुंचाया जा सके। दिल्ली के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 एमटी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ दुर्गापुर से अपने रास्ते पर है और उम्मीद है कि चार जून, 2021 को दिल्ली पहुंच जाएगी। तेलंगाना कोओडिशा के अंगुल से आने वाले अपने दूसरे ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 60.23 एमटी एलएमओ मिलेगा। हरियाणा को अपनी चौथी और पांचवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिलेगी जिसमें लगभग 72 एमटी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। ये ट्रेनेंओडिशा के अंगुल और राउरकेला से आ रही हैं। 85 टन के साथ एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस हापा (गुजरात) से निकल चुकी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए गुड़गांव पहुंच रही है।

मध्य प्रदेश (चौथी), उत्तर प्रदेश (10वीं), तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली के लिए और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रास्ते में हैं। कुल सात ट्रेनों में 422.08 मीट्रिक टन एलएमओ की ढुलाई की जा रही है।

कोरोना के खिलाफ जंग में ना हो डॉक्टरों की कमीः पीएम मोदी

» केंद्र सरकार ने दी कई फैसलों को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। संक्रमण के खिलाफ जंग में मानव संसाधन की बढ़ती मांग की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई अहम फैसलों को मंजूरी दी जिससे कोविड ड्यूटी में चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी।

इन फैसलों के तहत बड़ी संख्या में क्वालिफाइड डॉक्टर कोविड ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे। यह भी तय किया गया है कि मेडिकल इंटर्न्स की कोविड मैनेजमेंट में ड्यूटी लगाई जाएगी। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी टेली-कंसल्टिंग और हल्के लक्षण वाले मरीजों की निगरानी आदि में लगाया जाएगा, जिससे डॉक्टरों से काम का कुछ बोझ हटेगा। फाइनल ईयर पीजी स्टूटेंड्स रेजिडेंट्स के रूप में तब तक सेवा दे सकते हैं जब तक नया बैच नहीं आ जाता है। बी.एससी/जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेज का उपयोग सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम कोविड

नर्सिंग ड्यूटी में किया जा सकता है। जो डॉक्टर कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी कर लेंगे उन्हें सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। मेडिकल स्टूडेंट्स/ प्रफेशनल्स जो कोविड ड्यूटी करेंगे उनका पहले टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में भी शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रफेशनल्स जो कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी करेंगे उन्हें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कोविड नेशनल सर्विस सम्मान दिया जाएगा।

4 महीने के लिए स्थगित होगी नीट परीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी संकट और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नीट-पीजी परीक्षा कम-से-कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के अनुसार एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा हल्के कोविड-19 लक्षण वाले परीजों की मॉनिटरिंग के लिए ली जाएगी। बीएससी (नर्सिंग)/जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल-टाइम नर्सिंग ड्यूटी के लिए ली जाएंगी। नीट-पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने के लिए टाल दिया गया है और 31 अगस्त 2021 से पहले परीक्षा नहीं होगा।